संक्षिप्त

पुराने नोट बदलवाने को अभी भी आरबीआई दफ्तर पहुंच रहे लोग

नई दिल्ली। पुराने नोट बदलवाने की अवधि तो तारीख गुजरे ही खत्म हो गई हो लेकिन दिल्ली की आरबीआई बांध में पुराने नोट बदलने आए लोगों की भीड़ अभी भी लगी है. यहां पर नोट बदलवाने के लिए कई लोग दूसरे राज्यों से भी आए हैं पर अभी को नोट न बदले जाने से निराशा ही हाथ लगी. एक हजार रुपये बदलवाने आई महिला ने कहा कि वह खुद तो बीमार थी, पति को पैसे बदलवाने देनी ली वह सदमे में आ गई, इसी कारण खुद आई है. उन्होंने कहा कि अब यहां पर नोट नहीं बदले जा रहे हैं, अब क्या इसको क्रोम में लगा कर रखें. वहीं नोएडा के रहने वाले राहुल बोले कि उन्होंने हजार के दो नोट भगवान को चढ़ाए थे, नोट में पैसे चढ़ा उठा कर ले गया था इसलिए पहले नहीं जमा करा पाया. इसी तरह 786 के नोटों का कलेक्शन करने वाले व्यक्ति ने भी कहा कि वह नोट बदलवाने आया है, लेकिन नोट नहीं बदले जा रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले लालजीत सिंह ने एक लाख की सरकारी अवध में से अब जब यहां नोट बदलने आए हैं तो मना कर दिया गया. नोट बदलवाने आए कई लोगों का कहना था कि उनके रिश्तेदार की देहात हो गया था इसलिए वे पहले नोट नहीं बदलवा पाए।

चाकू मारकर 100 नंबर डायल किया, लगाया लूट का झूठा आरोप

नई दिल्ली। झगड़ा खुजराने पर आए एक युवक ने पहले चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया, फिर 100 नंबर डायल करके घर के अंदर घुसकर लूट की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो सीन उलटा निकला। वारदात में जिसे लुटेरा बताया था, उसके पांव में चाकू लगा था। पूरे मामले पर सूझ बूझ से काम लेकर लूट नहीं, बल्कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते पड़ोसियों में झगड़े का मामला है। इसी झगड़े को सुलझाने के लिए दो युवक अपने पड़ोसी युवकों के घर गए थे। वहां कहासुनी के चलते एक युवक को चाकू घोंपकर फरार हो गए थे। वह आरोप था कि इस केस में शिकायती खुद शिकार हो गए। पुलिस ने घायल करने वाले युवक और उसके दो साथियों के खिलाफ आईपीसी 307 का केस दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमने एक आरोपी के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। मजबूरी वश पर चाकू मारने के बाद पुलिस को सूची सूचना देने का हवाला उसी ने लगाया था।

ऑटो में महिलाओं को देखकर सवार हुआ था, रास्ते में लूटा गया

नई दिल्ली। ऑटो में लूटपाट करने वाले गैंग अपने साथ महिलाओं को भी लेकर चल रहे हैं, ताकि शिकार आसानी से मिलते में आ जाए। ऐसी ही एक वारदात मधुर विहार फेज-1 में सामने आई है, जहां ऑटो गैंग ने एक सवारी से पर्स, मोबाइल और कपड़े तक लूट लिए। फिर उसे आधी रात में बीच रास्ते पर छोड़कर चलते बने। पटना मैथुरी (उत्तर प्रदेश) में रहने वाले गौतम (19) के साथ हुई। वह नोएडा में किराए पर रहकर जॉब करता है। जनवरी की रात गांव से ट्रेन के जरिए अमंद विहार रेलवे स्टेशन उतरा। वहां से नोएडा जाने के लिए ऑटो रोका किया। गौतम के अनुसार, ऑटो में सवारी वाली सीट पर दो महिलाएं और एक युवक बैठा था, इसलिए उसे डर नहीं हुआ। 100 रुपये में नोएडा तक किराया तय हुआ। ऑटो मधुर विहार फेज-1 से होकर जा रहा था। रात के करीब 12 बजे थे। सुनसान रास्ते पर ऑटो रुक गया। बदमाशों ने उसकी जेब से 2 हजार रुपये, मोबाइल, एटीएम कार्ड, कपड़ों का बैग आदि लिया और ऑटो से उतार भाग गए। इस शिकायत पर मधुर विहार पुलिस ने लूटपाट का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कॉफी विद डी के निजामत-निर्देशक को मिली धमकी, कुछ सीन हटाने को कहा

नई दिल्ली। कॉफी विद डी के निजामत के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही धमकी की तरह से धमकी भरी कॉल मिलने की शिकायत दिल्ली पुलिस को की गई है। सोमवार को डायरेक्टर की ओर से नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस को लिखित शिकायत दी गई। पुलिस मुकदमा तौर पर मामले की जांच कर रही है।

सेंट्रल द्वारा तीन दिन फ्री शॉपिंग की घोषणा

नई दिल्ली। फैशन स्टोर श्रृंखला फ्यूचर ग्रुप के सेंट्रल ने 6 से 8 जनवरी 2017 तक 20 शहरों में अपने 33 आउटलेट में 3 दिन फ्री शॉपिंग की घोषणा की है। नया साल शुरू होने के अवसर, परिधान, फुटवेयर, हैंडबैग, स्पोर्टवेयर, जूते, बाल सिंगर, लिंगरी, पुरुषों के सामान, किताबें और खाद्यसामग्री से ये विभिन्न श्रेणियों में अविश्वसनीय डिस्काउंट पर 200 से अधिक ब्रांडों पर सबसे अच्छे सौदों के साथ 2017 में 3 दिन फ्री शॉपिंग के साथ सॉफ्टलिंक्स लोगों के बड़े खरीदारी का अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के लिए सेंट्रल पूरी तरह से तैयार है। तीन दिनों का यह फ्री शुरुआत ऑफिस सीरीज हर खरीदार का जायका बढ़ाएगा। इसमें कोई भी एक खरीदारी 8000 रुपए के परिधान, फुटवेयर, हैंडबैग, स्पोर्टवेयर, जूते, बाल सिंगर, लिंगरी, पुरुषों के सामान, किताबें और खाद्यसामग्री लेकर लेकर 4000 रुपए दे सकते हैं और एक आदमी 2000 रुपए के परिधान, 1500 रुपए किताबों की फ्री शॉपिंग वाउचर और 500 रुपये मूल्य के फ्यूचर पे मोबाइल प्रीपेड के रूप में दे 4000 रुपए भी वापस पा सकता है। पहली बार कोई उपभोक्ता यह सब मुहैया सकता है। सेंट्रल के मार्केटिंग हेड जितेन्द्रनाथ पांडे ने कहा, 3 दिन फ्री शॉपिंग हमारा प्रयास है हमारे ग्राहकों को खरीदारी का उत्साह उपभोक्ता करने का जो पहले कभी देखा न गया हो। फैशन के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए शहरों आगे और मार्केटिंग विशेषज्ञ पेश करने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ सेंट्रल की स्थापना हुई थी। अब 3 दिन फ्री शॉपिंग के साथ उपभोक्ता न केवल सौदेबाजी लाभ पा सकते हैं बल्कि वे उन्हें लगभग मुफ्त में पा सकते हैं।

'आप' का पीएम मोदी से सवाल, पेटीएम से कितना पैसा लिया ?

नई दिल्ली। नोटबंदी का मुद्दा आने से विरोध कर रही आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेटीएम और जियो को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी की नेता अलका पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पेटीएम और जियो का प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, अब पेटीएम कंपनी की सफाई में सफाई के तौर पर भी दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी के नेता पेटीएम का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अलका पांडेय ने कहा कि सोमवार को राजेंद्र नगर विधानसभा में कंपनी के एक नेता द्वारा में पेटीएम के इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं, आप ने सवाल किया कि क्या कंपनी पेटीएम की सेल्स टीम बन गई है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देखने में आया है कि पेटीएम से 8 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं यानी पेटीएम को 120 करोड़ का मुनाफा हुआ है.

अलका पांडेय बोलीं कि क्या मोदी जी का paytm को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि पेटीएम में कैश नहीं है? सरकारी बैंक के खातों को मोदी जी और

कंपनी जी क्यों नहीं प्रमोट करते? उन्होंने कहा कि यह सब जानते हैं कि paytm के सबसे बड़े विज्ञापन चाहनेवाले कंपनी के लोग हैं, तो क्या मोदीजी और कंपनी की paytm से कोई डील चल रही है?

आप आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए -

मोदी जी ने paytm से कितना पैसा लिया है?

कंपनी अपनी राजनीतिक सभाएं paytm से स्पांसर क्यों करा रही है?

क्या इससे डाटा सिक्योरिटी का खतरा नहीं है?

किसी सरकारी वॉलेट को क्यों नहीं प्रमोट कर रही सरकार?

मनोज तिवारी पर साधा निशाना

वहीं आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने मनोज तिवारी के पैसेंटी वाले बयान पर सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा कि आप एक पूरे हुए प्रतिनिधि हैं आपके पंद्रह कहां है, उससे सवाल कीजिए, मौजूदा है कि मनोज तिवारी ने इंदौरी की सुनिधी में जाकर कहा था कि वह अब पैसेंटी के जरिए काम करेंगे. त्रिपाठी ने कहा कि अगर वो दिल्ली के विकास में सहयोग करना चाहते हैं तो अनधिकृत कालोनियों के काम से जुड़ी जो पहाड़ी कोर्ट सरकार के पास नहीं हैं उन्हें पास करवाएं, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आज कल उनके पीएम भी एक अच्छे कलाकार साबित हो रहे हैं।

भय के साए में मुलायम-शिवपाल के करीबी, तख्तापलट के बाद बदले समीकरण

लखनऊ। शिव के पक्ष में बोलने पर बेटे के, इस बयान ने सपाइयों को कड़ा संदेश दिया दिया है। आजम मंत्रिक की सुरक्षा वापस हो जाने के बाद उन पदाधिकारियों को हटा दिए जाने का डर सता रहा है जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं। सपा कुनबे में लखनऊ में चल रही रार का असर वाराणसी में कल उस समय पहुंच गया, जबकि मुलायम के करीबी माने जाने वाले एमएलसी आजम मंत्रिक की वाई श्रेणी सुरक्षा एक झटके में हटा दी गई।

स्थानीय सपाइयों को इससे अंदाजा हो गया कि रार किस स्तर तक बढ़ चुकी है। लखनऊ छावनी लखनऊ के इलाके की असली तस्वीर देखने के लिए अहम दिखाने टीवी सैटों से चिपके रहे। मनोज पांडेय को हटाकर रविदास को ही युवजन सभा का महानगर अध्यक्ष राहुल पांडेय के समर्थकों को भरोसा नहीं कि वे पद कब तक बरकरार रहेगा। कारण ये है कि जिस शिवपाल यादव के आशीर्वाद से उन्हें सीधा को वे पद मिला है, उन्हीं शिवपाल यादव के सपाट को लखनऊ में अखिलेश द्वारा नियुक्त नए प्रदेशाध्यक्ष परेश ने हाशिया लिया और शिवपाल की नेमप्लेट व सामान तक पंडाल के समर्थकों ने बाहर फेंक दिया।

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में अपना की जगह महानगर अध्यक्ष बने प्रवेश यादव के नजदीकी भी समझ नहीं पा रहे कि अब उनके साथ क्या होगा। प्रवेश एमएलसी आजम मंत्रिक के नजदीकी माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के आशीर्वाद से शहर ही में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बने राहुल चौपाटी का शिवपाल भी ढोल रहा है।

अखिलेश व रामगोपाल समर्थक मंत्री यादव को शिवपाल ने तीन महीने पहले रार के पहले राउंड में ही पार्टी से बाहर कर दिया था। तीन महीने पद खाली रहा और जिससे हमले हो राहुल चौपाटी को महानगर अध्यक्ष बनाने की चौपड़ा की गई।

लखनऊ में हुए तख्तापलट के बाद बने समीकरणों में मंत्री यादव के समर्थक खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि महानगर अध्यक्ष पद मंत्री को फिर से मिल सकता है। सपा के रार पर स्थानीय नेता कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पिता या पुत्र में से किसी एक का ही साथ देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ज्यादातर सपाई अखिलेश के समर्थक होने के बावजूद ये चाहते हैं कि रार खत्म हो जाए और चाचा भतीजे ही नहीं भी आएं, मगर पिता व पुत्र एक हो जाएं।

टीचरों की भर्ती के लिए नए नियम तैयार कर रहा है शिक्षा विभाग

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 17 हजार गेस्ट टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के लिए शिक्षा विभाग नए नियम तैयार कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाबी पार्टी में पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर गेस्ट टीचरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि आंदोलन में दूसरे विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली सरकार आजकल गेस्ट टीचरों से खासी नाराज चल रही है। उसका कारण यह है कि पिछले तिनों गेस्ट टीचरों के हुए एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने सरकार के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन कर दिया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि शामिल हुए थे। टीचरों के प्रदर्शन पर सरकार ने खासी नाराजगी जताई थी और कहा था कि हर साल गेस्ट टीचरों का हर साल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू सिस्टम को बदला जाएगा और इसमें इस बार पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सरकार उसी आधार पर गेस्ट टीचरों की भर्ती करेगी। दूसरी ओर सरकार के खिलाफ गेस्ट टीचरों का चल रहा आंदोलन जारी है। इन टीचरों ने हाल ही में दिल्ली सरकार के खिलाफ कनॉट प्लेस में एक बैठक की और प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया गेस्ट टीचर असोसिएशन ने किया। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण रोहड़िया ने दावा किया कि उनके आंदोलन में दूसरे विभागों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि गेस्ट टीचरों की भर्ती पर सरकार जो भी नियम बना ले, लेकिन ऐसे नियम सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही तय कर दिए हैं और उसी आधार पर गेस्ट टीचरों को नियुक्ति होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने गेस्ट टीचरों को हटाने की कवायद की तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन जारी कर देंगे।

निगम चुनाव: बीजेपी का दिल्ली वालों से सीधा संवाद

नई दिल्ली। अगस्त और मार्च में होने वाले तीनों नगर निगमों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीजेपी के नेता दिल्ली के लोगों से सीधे संवाद की तैयारी कर रहे हैं। मिलजुल पार्टी नेता पार्टी के जिला नेताओं व कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में जुटे हैं। ऐसे चल रहे कार्यक्रमों में नेताओं व कार्यकर्ताओं को पूरी तरह ट्रेंड किया जाएगा कि जब वे आम जन से मिले तो उन्हें क्या संवाद करना होगा। वैसे पार्टी इस बात से खासी खुश नजर आ रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथोहाथ लिया है।

निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी दिल्ली के लिए जिस नेता की तलाश कर रही थी, वह विजेंद्र अभिषेक मनोज तिवारी के रूप में उसे मिल गया है। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन मनोज जब दिल्ली की सड़कों और गलियों में घूमते से पार्टी नेताओं ने यह लिख कि उनका फैसला एकदम ठीक है। अध्यक्ष बनते ही मनोज तिवारी फुल फार्म में हैं। कल उन्होंने इंदौरी सुन्नी बस्ती में जाकर रात गुजारी और लोगों से सीधा संवाद किया। मनोज को सुनने के लिए वहां पैंफ्रों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ने शाम से ही कई जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें नेताओं व कार्यकर्ताओं को इस बात को जानकारी दी गई कि एमसीडी चुनाव को देखते हुए उन्हें किस तरह जनता से जुड़ना है। ऐसे सम्मेलनों में पार्टी के अध्यक्ष नेता डॉ. अनिल जैन, विद्यासागर, रमेश बिधूड़ी, ओमप्रकाश, जयप्रकाश, विनय शर्मा, आकाश सिंह, विभिलेश सिंह आदि भी मौजूद थे।

इन सम्मेलनों में बताया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए नहीं जनसेवा के लिए राजनीति में है और यह ही उस मूल अंतर है जिसके चलते बीजेपी आज जिस भी सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कि जब निगम चुनावों को देखते हुए अगली चार माह सभी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन को समर्पण के हैं। इन चार माह में महिला से लेकर युवा कार्यकर्ता तक सभी को श्रम करना होगा और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना होगा। दूसरी ओर बीजेपी को दिल्ली बीजेपी के लिए मनोज तिवारी के रूप में कार्यकारी नेता मिल गया है। वरना पिछले कई चुनावों से ऐसा होता रहा है कि जिस को भी पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता, उसका विरोध जरूर होता। दिल्ली बीजेपी में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पूर्वांचली को अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल से मंजूर कर लिया है। सबसे दिलचस्प बात यह ही रही है कि जनता का भी उन्हें जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है। जिससे पार्टी उम्मीद जता रही है कि निगम चुनाव में उसकी जीत आसान होगी।

गेस्ट टीचर: दिल्ली सरकार ने नियम बनाने शुरू किए

नई दिल्ली, दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 17 हजार गेस्ट टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने के लिए शिक्षा विभाग नए नियम तैयार कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाबी पार्टी में पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर गेस्ट टीचरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि आंदोलन में दूसरे विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं गेस्ट टीचर।

दिल्ली सरकार आजकल गेस्ट टीचरों से खासी नाराज चल रही है। उसका कारण यह है कि पिछले तिनों गेस्ट टीचरों के हुए एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने सरकार के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन कर दिया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि शामिल हुए थे। टीचरों के प्रदर्शन पर सरकार ने खासी नाराजगी जताई थी और कहा था कि हर साल गेस्ट टीचरों का हर साल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू सिस्टम को बदला जाएगा और इसमें इस बार पुराने गेस्ट टीचरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सरकार उसी आधार पर गेस्ट टीचरों की भर्ती करेगी। दूसरी ओर सरकार के खिलाफ गेस्ट टीचरों का चल रहा आंदोलन जारी है। इन टीचरों ने हाल ही में दिल्ली सरकार के खिलाफ कनॉट प्लेस में एक बैठक की और प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया गेस्ट टीचर असोसिएशन ने किया। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण रोहड़िया ने दावा किया कि उनके आंदोलन में दूसरे विभागों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि गेस्ट टीचरों की भर्ती पर सरकार जो भी नियम बना ले, लेकिन ऐसे नियम सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही तय कर दिए हैं और उसी आधार पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने गेस्ट टीचरों को हटाने की कवायद की तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन जारी कर देंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस की फी ऑनलाइन जमा होगी

नई दिल्ली। अब ड्राइविंग लाइसेंस की फी जमा करने के लिए दिल्ली वासियों को लाइन में नहीं लगना होगा और न ही बार-बार चक्कर काटने होंगे। रविवार को सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फी जमा की जा सकेगी। अगले चार जनवरी के बाद से ही सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फी जमा कराने पूरी व्यवस्था होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अपने ट्वीट में लिखा दिल्ली सरकार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और फी पेमेंट की सुविधा मुहैया करा रही है।

कराबल नगर : जल मंत्री के इलाके में नहीं 5 दिन से पानी

नई दिल्ली। जल मंत्री के इलाके में पानी की किल्लत! कराबल नगर के एक हिस्से में करीब एक हफ्ते से जैसे पानी का सूखा पड़ा हुआ है। यहां के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। जल मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कराबल नगर से ही विधायक भी हैं। उन्हें लोगों को राहत देनी चाहिए लेकिन उनके पास देने के लिए लगभग रोने के सिवाय कुछ नहीं है। पश्चिमी कराबल नगर को 9 नंबर लेन के भी कालोनी में 30 परिवार रहते हैं। पिछले 5 दिनों से यहां न तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी की सप्लाई की गई है, न कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सोमवार शाम को कुछ घरों को पानी मिला लेकिन सिर्फ 15 मिनटों के लिए। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के पास पीने पानी के इंतजाम के अलावा कोई विकल्प नहीं। यह पानी पीने योग्य सेवा से दूर, कपड़े धोने तक के लायक नहीं है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग वॉटर प्यूरिफायर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते, जिसका कई लोग पास की कॉलोनियों से बोतलें भर कर पानी लाने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के मनुष्य विहार कार्यालय ने अब तक पानी सप्लाई बाधित होने की वजह नहीं बताई है। बोर्ड का कहना है कि अब तक इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है उधर बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल का सिलसिला दर्ज कराई जा चुकी है। जल बोर्ड का कहना है कि सेमिया विहार की वॉटर सप्लाई लाइन के टूटने की वजह से जल आपूर्ति बाधित है। जल मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है सोमवार को कई जगहों पर पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई और मंगलवार शाम तक लोगों को पूरा पानी मिलने लगेगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है, हमें हमेशा अनियमित सप्लाई मिलती है।

दुविधा

ज्यादा डॉक्टर ड्यूटी के दौरान किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करते हैं.....

डॉक्टरों पर हो रहे हमलों से परेशान सरकार बनाएगी सख्त कानून

नई दिल्ली। डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमले सरकार के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। मरीजों के रिश्तेदारों या परिजनों द्वारा के साथ मारपीट और हिंसा की खबरें आए दिन आती रहती हैं। इसलिए अब सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। हीलिंग नेशिकल असोसिएशन के अनुसार के मुताबिक 75% से ज्यादा डॉक्टर ड्यूटी के दौरान किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करते हैं।

सरकार ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद सरकार ने साल 2015 में एक इंटर-मिनिस्टरीयल कमिटी बनाई थी। कमिटी से ऐसे मामलों और शिकायतों की जांच करने को कहा गया था। इस कमिटी ने अपने सुझावों में कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष पेश करना चाहिए। एक सूत्र ने बताया कि प्रस्तावित कानून में कुछ कड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं जैसे कि डॉक्टर या हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी पर हमले को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। देश के तकरीबन 18 सेक्टरों में पहले से ऐसे कानून मौजूद हैं। हालांकि, कानून पर प्रभावी ढंग से अमल न होने की वजह से डॉक्टरों को मरीजों के परिजनों के गुस्से और बदसूरती का शिकार बनना पड़ता है। कमिटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि राज्यों में बाकी कानूनों के साथ यह कानून भी बनाकर लागू किया जाए।

इससे पहले इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने पूरे देश में एक सर्वेक्षण की थी। इसके मुताबिक ये सामने आया था कि ज्यादातर डॉक्टर इमर्जेंसी सर्विस देने के दौरान हिंसा का शिकार होते हैं। 48.4% हिंसा की वारदातें आईसीयू वार्डों या वार्डों के दौरान होती हैं। इन घटनाओं के पीछे प्रमुख वजह होती है मौजूदगी पड़ताल या फिर मरीज को देखने में हो रही देरी। अटेंडेंट्स में वार्डों में फोन और फोन न मिलने तक बीटों न दिया जाना भी मारपीट के पीछे बड़ी वजहें होती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 66.33% मामलों में मरीज की देखभाल कर रहे उनके परिजन या रिश्तेदार डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं।

पांच जनवरी से योगदा शताब्दी वर्ष समारोह

नई दिल्ली। योगी कथामृत के लेखक परमहंस योगानंदजी द्वारा स्थापित संस्था योगदा सत्संग पांच जनवरी, 2017 से लेकर 22 मार्च, 2018 तक अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रही है। इस अवसर की जानकारी देते हुए योगदा के स्वामी ईश्वरानंद गिरि ने बताया कि परमहंस योगानंद जाकी को नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में विशेष कार्यक्रमों के साथ आयोजन किया जा रहा है। नोएडा आश्रम में राजयोग मिशन के सचिव स्वामी शंकरानंद जी प्रमुख अतिथि होंगे। साथ ही विश्वव्यापी मिशन के प्रमुख स्वामी तेजोमयानंद जी मुंबई में आयोजन की अगुवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 200 से अधिक स्थानीय केंद्रों के माध्यम से, एक आध्यात्मिक और मानवीय संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। योगदा के निदेशक और पूर्व राजयोग योगदा कक्षाओं में कहा कि मैं लंबे समय से शिष्य योगदा अध्यापकों होने तथा योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने निजी और कार्यक्षेत्र में अपनाने के अपने व्यक्तिगत अनुभव से मौलिक सत्यतत्व के साथ-साथ परम संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष में योगदा स्वामी जी के संदेश को समस्त भारत में पहुंचाना चाहती है। साथ ही यह कामना चाहती है कि क्रिया योग विज्ञान के अभ्यास से हरेक जीवन सुखमय हो सकता है।

संक्षिप्त खबर

पांच जनवरी से योगदा शताब्दी वर्ष समारोह

नई दिल्ली। योगी कथामृत के लेखक परमहंस योगानंदजी द्वारा स्थापित संस्था योगदा पांच जनवरी, 2017 से लेकर 22 मार्च, 2018 तक अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रही है। इस अवसर की जानकारी देते हुए योगदा के स्वामी ईश्वरानंद गिरि ने बताया कि परमहंस योगानंद जयंती को योगदा, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में विशेष कार्यक्रमों के साथ आरंभ किया जा रहा है। योगदा आश्रम में रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ स्वामी गंभीरानंद जी प्रमुख अतिथि होंगे। साथ ही चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी तेजोमयानंद जी मुंबई में आयोजन की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 200 से अधिक ध्यान केंद्रों के माध्यम से, एक आध्यात्मिक और धर्मार्थ संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। योगदा के निदेशक और पूर्व राज्यपाल केएन काटजू ने कहा कि मैं लंबे समय से क्रिया योग अभ्यासी होने तथा योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने निजी और कार्यक्षेत्र में अपनाने के अपने व्यक्तिगत अनुभव से मौलिक सफलता के साथ-साथ परम संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष में योगदा स्वामी जी के संदेश को समस्त भारत में पहुंचाना चाहती है। साथ ही यह बताना चाहती है कि क्रिया योग विज्ञान के अभ्यास से हरेक जीवन सुखद हो सकता है।

बीजेपी ने सरकारी कर्मचारियों को त्राहि-त्राहि करने को मजबूर किया

नई दिल्ली। स्वामी दयानन्द अस्पताल में पिछले 3 महीने से डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन न मिलने के कारण पिछले कई दिनों से सुबह 10.00 बजे से लेकर दोपहर 1.00 बजे तक हड़ताल पर है। इन कर्मचारियों ने अपने हड़ताल को सफल बनाने हेतु नेता विपक्ष वरुण कौर को आमंत्रित किया। इस अवसर पर नेता विपक्ष सुश्री वरुण कौर, विनय पराशर, राजा सिंह पंवार एवं आशीष पैनली पूर्व निगम पार्षद आदि हड़ताल में शामिल हुए। इस अवसर पर सुश्री वरुण कौर जी ने कहा कि डॉक्टरों को पिछले तीन महीनों का वेतन नहीं मिला है इस कारण डॉक्टरों एवं नर्सों को अपना घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।

तकनीकी समस्या के चलते फिर प्रभावित रही मेट्रो, यात्री परेशान

- रफ्तार थमने का असर ब्लू लाइन के अन्य स्टेशनों पर भी पड़ा
- ट्रैक की जरूरी मरम्मत की वजह से लोगों को आई परेशानी

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा मंगलवार को लगातार बाधित हो रही है। इस रूट पर यात्री मेट्रो के रुक-रुक कर चलने की शिकायत कर रहे हैं। वैशाली और नोएडा सिटी सेंटर से द्वारका की ओर आ रही मेट्रो यमुना बैंक पर 15-20 मिनट रुककर चल रही है। रफ्तार थमने का असर ब्लू लाइन के अन्य स्टेशनों पर भी पड़ रहा है। डीएमआरसी के अनुसार द्वारका की तरफ जाने वाली अप लाइन पर मंगलवार सुबह करीब 11.20 बजे ट्रेनों के लिए 20 किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय कर दी गयी।

अधिकारी ने बताया कि ओवरहेड वायरिंग से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए ऐहतियात किया गया। कार्य प्रगति पर है और गति सीमा पर अब भी नियंत्रण कायम है। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा सिटी सेंटर और वैशाली की तरफ जाने वाली ब्लू लाइन में अक्सर दिन इस तरह की समस्या सामने आती रही है।

पिछले कई दिनों से तकनीकी या निर्माण कार्य के चलते यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनती रही है। इससे पहले इसी रूट पर पिछले दो रविवार से सेक्टर 12 से द्वारका 3 बजे के बीच ट्रैक की जरूरी मरम्मत भी की गई थी। दिल्ली मेट्रो प्रशासन की तरफ से परिचालन के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने की बात कही गई थी।

अज्ञात वाहन की टक्कर से पत्रकार कोमा में

सन स्टार संवाददाता

नोएडा। वरिष्ठ पत्रकार आर.आर. चतुर्वेदी जो पिछले 20 सालों से पत्रकारिता में ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं। उनका एक जनवरी 2017 को नोएडा सेक्टर-137 में एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी जिसकी वजह से उनको काफी चोट आई है।

सिर में गंभीर चोट आने से उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने चतुर्वेदी जी को गंभीर स्थिति में नोएडा सेक्टर -137 स्थित मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की टीम ने तुरन्त आईसीयू में भर्ती किया।

चतुर्वेदी जी का इलाज चलते दो दिनों से आईसीयू चल रहा है। अभी तक चतुर्वेदी जी को होश नहीं आया है। डॉक्टरों का कहना है कि चतुर्वेदी जी चेतना कब तक वापस आयेगी ये कहना जानलेवा होगा।

अनुच्छेद 370 पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। क्या जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के बिना जम्मू-कश्मीर में किसी संवैधानिक संशोधन का लागू नहीं होना न्यायाधीशों के लिए वहां भारतीय संविधान के क्रियान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता। संविधान आदेश 1954 को चुनौती देने संबंधी एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृश्य ऐसा लगता है कि याची को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए थी। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। ये जनहित याचिका दिल्ली निवासी वकील सुरजीत सिंह ने दायर की है। याची ने संविधान आदेश 1954 को चुनौती दी है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 368 के एक प्रावधान को जोड़ा गया है। कहा गया है कि ऐसा कोई भी संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में उस समय तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत उसे राष्ट्रपति के आदेश से लागू नहीं किया जाए। याची ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट के न्यायाधीश भारतीय संविधान को लागू करने को बाध्य नहीं हैं।

जेएनयू कार्यसमिति की बैठक, विरोध में उतरे छात्र

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यकारी समिति की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद होने की संभावना है। छात्र संगठनों ने विरोध का एलान किया है वहीं दूसरी ओर जेएनयू प्रशासन और शिक्षक संगठनों ने सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। जेएनयू प्रशासन ने तीन दिन के अंदर दूसरी बार पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कार्यसमिति के बैठक स्थल पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगाने की मांग की है। ज्ञात हो कि ऐसा पहली बार है कि जब प्रशासन ने इस तरह की किसी बैठक में सुरक्षा के लिए लिखित रूप से पुलिस से मदद मांगी है। 26 दिसंबर को विद्वत परिषद की बैठक में प्रशासनिकारी छात्रों ने कन्वेंशन सेंटर के गेट को तोड़कर हंगामा किया था जिसके बाद प्रशासन ने आठ छात्रों को निलंबित कर दिया है। कार्यकारी परिषद की मीटिंग का विरोध के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर सभी छात्र संगठनों ने सोमवार को रणनीति बनाई। एनएसयूआइ के समर्थन में कुछ छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष सौराल राजिद ने एक ओपन लेटर लिखकर सभी छात्रों को एकजुट होने के लिए कहा है। वहीं जेएनयू प्रशासन ने प्रशासनिक भवन के बाहर कार्यक्रम आयोजित करने पर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष को चेतावनी दी है। प्रशासन ने मीडिया के नाम लिखे पत्र में लिखा है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी प्रशासनिक भवन के बाहर कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदर्शन जारी है। इसलिए अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जेएनयू के प्राक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि आगामी पर जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी यह आरोप लगाते हैं कि जेएनयू के अधिकारी नहीं मिले लेकिन हम लोगों ने सुबह नौ बजे आधा घंटा तक उनका इंतजार किया है लेकिन कोई मिलने नहीं आया। निलंबित छात्रों ने प्राक्टर के समक्ष रखा पक्ष:- निलंबित छात्रों ने सोमवार को प्राक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखा। पुनर्घटित अनुशासन समिति के सदस्य छात्र मुखपाल ने बताया कि हम प्राक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए गए थे। हमने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि बिना किसी प्रामाणिक सबूत और आधार के आप हमें कैसे निलंबित कर सकते हैं। प्रशासन का यह निर्णय अतिरेकतापूर्ण है। यह एक बार सिद्ध हो चुकी है कि साक्ष्यपरक ने जातिवाद वाले वर्षों से चला आ रहा है। हम इसके खिलाफ अपनी बात रख रहे थे। प्रशासन निलंबन का निर्णय लेकर हमें डराना चाहता है। कार्यकारी समिति की बैठक का हम जोरदार विरोध करेंगे।

सभी खेल संस्थाओं से नेताओं का हस्तक्षेप खत्म हो: आप

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए देश की तमाम खेल संस्थाओं से राजनीतिक पार्टियों का प्रभुत्व खत्म करने और राजनेताओं का हस्तक्षेप खत्म करने की मांग की है। मंगलवार है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों लागू नहीं करने के चलते बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को बर्खास्त कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडेय ने कहा, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि देश की तमाम खेल संस्थाओं से न केवल राजनीतिक पार्टियों का प्रभुत्व खत्म होना चाहिए बल्कि नेताओं का हस्तक्षेप भी पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। दिलीप ने कहा, जस्टिस लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों के मूल भाव को देश की सभी खेल संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक राहुल मेहरा जैसे संघर्षशील लोगों के लिए भी एक जीत की तरह है जो लगातार देश की खेल संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से आजाद करवाने और खेल की बेहतरी के लिए अदालत से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। दिलीप ने साथ किया कि आप पूर्व में भी डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती रही है क्योंकि खेल संस्थाओं में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन ने देश में खेल संस्थाओं और खेल की प्रतिभाओं को बर्बाद कर दिया है। खेल संस्थाओं में भ्रष्टाचार ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बल्कि देश में खेल का कमजोर ढांचा भी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि खेल संस्थाओं को अच्छे तरीके से चलाने के लिए खेल माफिया माफिया वाले किसी पूर्व खिलाड़ी को ही इसकी कमान सौंपी जानी चाहिए क्योंकि एक खिलाड़ी या केवल खेल को अच्छे तरह समझता है बल्कि वह खिलाड़ियों की जरूरतों को भी बखूबी जानता है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि देश में खेलों से जुड़ा भी एक मजबूत कानून हो ताकि न केवल खेल संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके बल्कि खेल प्रतिभाओं के साथ भी न्याय हो सके।

कांग्रेस ने बजट बैठक का किया बहिष्कार, बजट की प्रति फेंकी

- शाहदरा दक्षिणी जोन चेयरमैन और स्टेंडिंग कमेटी उपाध्यक्ष महेंद्र आहूजा ने किया कांग्रेस के कदम की निंदा
- शाहदरा नार्थ जोन चेयरमैन ने विशेष पैकेज दिए जाने पर दिया जोर
- बजट पर चर्चा को हुई निगम की स्टेंडिंग कमेटी की विशेष बैठक
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्टेंडिंग कमेटी की बजट बैठक का कांग्रेस ने ना केवल बहिष्कार किया, बल्कि बजट से जुड़े दस्तावेज ही उठाकर

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। स्टेंडिंग कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी और निगम आयुक्त के टेबल के आगे जमीन पर पटक दिए। मंगलवारी बीजेपी की स्टेंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र आहूजा और शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन देवेंद्र कुमार ने विपक्ष के इस कदम की आलोचना की। श्री आहूजा का तर्क था कि जिन दस्तीज आर्थिक हालात के दौर से विपक्ष गुजर रहा है,ऐसे में विपक्ष का ये भी दायित्व बनता है कि वजह बजट को अंतिम रूप दे,लेकिन जो विपक्ष की भूमिका रही जनता अपने वाले निगम चुनाव में कांग्रेस को जवाब देने का काम करेगी।

वहीं निगम के शाहदरा नार्थ जोन के चेयरमैन मनोज लाली ने नार्थ जोन की दयनीय हालत को देखते हुए विशेष पैकेज दिए जाने पर जोर दिया। उनका तर्क था कि शीला सरकार के दौर में अनुनगर के विकास के लिए मलुन विकास बोर्ड का गठन किया था,लेकिन केजरी वाल सरकार के द्वारा बोर्ड को भंग कर दिया गया और अब पैसा कहां जा रहा है कोई बताने वाला नहीं है।

निगम के पटपड़गंज मुख्यालय में आयोजित बजट बैठक के दौरान कांग्रेस से विपक्ष की नेता वरुणा कौर का तर्क था कि विपक्षी सदस्यों के द्वारा सदन और सदन के बाहर लिखित रूप से समय से निगम की विशेष और तदर्थ समितियों के गठन की मांग लगातार उठायी गई,लेकिन पूरा एक साल बीत जाने के बाद समितियों का गठन किया गया,जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेखा समिति को निगम की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है उसका अभी तक भी गठन नहीं किया गया है। लेखा कमेटी से जुड़े तमाम कार्य रुके हुए हैं। निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के जो चुनाव हुए वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। निगम प्रशासन अपने स्तर को बैलेंस नहीं दे पा रहा है ऐसे में निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल के डाक्टर और स्टाफ लगातार भारत प्रदर्शन की विवश है।

सदन हालात को देखते हुए कांग्रेस इस बजट बैठक का बहिष्कार करती है। वहीं इस कदम को निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन देवेंद्र कुमार और स्टेंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र आहूजा ने कड़ी आलोचना की। श्री आहूजा ने कहा कि कांग्रेस बजट पर चर्चा से पीछे भाग रही है जो कि पूरी तरह से गलत है।

जोन चेयरमैन देवेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रही है। जबकि जो निगम के मौजूदा दयनीय हालात हैं वह कांग्रेस की देन है। वहीं निगम के नार्थ जोन के चेयरमैन मनोज लाली ने कहा कि बिना हालात में बजट रखा जा रहा है वह किसी से छिपा नहीं है।

पेश बोधकर सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जिस वजह संयुक्त निगम के पार्षद होने से लगता था ना जाने कैसे क्षेत्र का विकास होगा। दुर्भाग्य पूर्ण पहलू ये है कि जिस मनुना पार बोर्ड के गठन से विकास की उम्मीद थी उसे ही भंग कर दिया गया। इस दौरान निगम की वर्क कमेटी के अध्यक्ष संजय कीर्तिक,हैल्थ कमेटी अध्यक्ष उषा देवानी शास्त्री और निगम की उद्यान कमेटी अध्यक्ष शकीला बेगम एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवा समिति अध्यक्ष चंद्र शर्मा ने बजट पेश किया।

विश्वास नगर में अब होगा नए सिरे से सर्वे

उच्च न्यायालय ने सुनाया फरमान

- स्टेंडिंग कमेटी उपाध्यक्ष ने कहा सर्वे पूरा होने से पहले ना हो किसी तरह की सीलिंग

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। एमसीडी आज विश्वास नगर स्थित स्केल टैन्ड एंड ट्रेडर्स की याचिका पर उच्च न्यायालय ने विश्वास नगर औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों का नए सिरे से सर्वे किए जाने के आदेश दिए है। इस बीच अदालत ने एमसीडी के द्वारा सात साल पर प्रदूषण के मामले को लेकर दुकान नए निर्माणों पर शामिलों को गंभीरता से सुना। याचियों की मांगें तो ये रहात देने वाला कदम है। इस कदम से क्षेत्र की दो हजार औद्योगिक इकाईयों को ये कदम राहत देने वाला है। करीब चार हजार श्रमिकों को इस कदम से राहत मिलेगी। इधर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र आहूजा ने सर्वे का काम पूरा होने तक क्षेत्र में किसी तरह की सीलिंग अथवा नोटिस न दिए जाने का निगम अधिकारीयों से आग्रह किया है।

श्री आहूजा ने पत्र की प्रति निगम महापौर,अतिरिक्त आयुक्त फैक्ट्री लाइसेंस,उपायुक्त फैक्ट्री लाइसेंस,उपायुक्त शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र और अध्यक्ष एसोसिएशन आफ विश्वास नगर स्माल स्केल एंड टेन्डर्स एसोसिएशन को भेजी है। श्री आहूजा ने कहा कि वह अदालत के निर्णय का सम्मान करते है,यदि पुराने सर्वे के आधार पर एक बार फिर से विश्वास नगर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाता है तो यह स्वागत योग्य कदम होगा। निगम के अधिकारीयों को चाहिए किसी सर्वे में किसी तरह की अड़चन आड़े नहीं आए इसके लिए सर्वे का वातावरण बनाए।विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि रेजीडेंट एसोसिएशन और स्माल स्केल एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से अदालत में चुनौती दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में 5300 औद्योगिक यूनिटों में से 4500 यूनिटों पर औद्योगिक इकाईयां संचालित हो रही है। वास्टर प्लान 2021 में इस बात का उल्लेख है कि यदि किसी औद्योगिक एरिया में 70 प्रतिशत यूनिटों पर औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही है तो उसे दिल्ली सरकार औद्योगिक क्षेत्र घोषित करे। चूंकि एरिया के 70 फीसदी से अधिक यूनिटों पर औद्योगिक इकाईयां संचालित हो रही है तो क्षेत्र को राजधानी के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों की भांति औद्योगिक एरिया घोषित किया जाना चाहिए ताकि इन औद्योगिक संस्थानों से जुड़े 40 हजार लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आने न आए।

डीटीसी बसों का किराया न घटने से लोगों में रोष: गुप्ता

सन स्टार संवाददाता

नई दिल्ली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मदास के जितेंद्र गुप्ता के अनुसार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वादे के बाद भी डीटीसी बसों का किराया न घटाए जाने से लोगों में रोष है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से डीटीसी की बसों के किराये घटाने का ऐलान किया था लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल की इस प्रस्ताव पर सहमति न मिल पाने के कारण फैसला अटका हुआ है।

जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता को अच्छा संदेश भी कि यह निर्णय पहली जनवरी से लागू हो जाएगा। परंतु, दिल्ली सरकार इस निर्णय को लागू करने में विफल रही है।

वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, उसके अनुसार इस निर्णय को लागू करने में अभी और कई दिन लगेंगे। गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय इस बात का द्योतक है कि केजरीवाल सरकार अपने राजनीति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सारा ध्यान अन्य राज्यों की चुनावी राजनीति पर लगा रही है। वह डीटीसी बसों के किराये कम करने जैसे साधारण प्रशासनिक निर्णयों को कार्यरूप देने में भी अक्षम है।

उपराज्यपाल ने 16 दिसम्बर को डीटीसी बसों के किराये कम करने के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने जनता को आश्वस्त किया था कि वह पहली जनवरी से इन आदेशों को अमल में ले आएगी। परंतु, समय-सीमा बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रस्ताव तैयार तक नहीं किया गया। अभी विभिन्न विभागों से इस संबंध में टिप्पणियां मंगाई गई हैं। इसके आने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इन औपचारिकताओं के बाद ही डीटीसी बसों का किराया घटाया जा सकता है।